

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उतरांचल, उतराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण गुरुवार 09 अप्रैल 2026 वर्ष-9, अंक-74 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com  www.facebook.com/krantisamay1  www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

गुजरातियों पर किए कमेंट के लिए खरगे ने मांगी माफी

● बोले-हमेशा रहेगा सम्मान, बयान को गलत पेश किया जा रहा

नई दिल्ली (एजेंसी)। केरल विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान गुजरात के लोगों पर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि उनकी टिप्पणियों को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वह खेद व्यक्त करते हैं। खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, हाल ही में केरल में दिए गए मेरे एक चुनावी भाषण की कुछ टिप्पणियों को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। फिर भी, मैं अपनी तरफ से जिम्मेदारी के साथ खेद व्यक्त करता हूँ। गुजरात के लोगों के प्रति मेरे मन में हमेशा सर्वोच्च सम्मान रहा है और हमेशा रहेगा। वहां के लोगों की भावनाओं को आहत करना मेरा कभी उद्देश्य नहीं था। दरअसल, पिछले दिनों केरल चुनाव के दौरान प्रचार करते हुए खरगे ने एक रेती को संबोधित किया था, जहां पर उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा था। हालांकि, इस दौरान उन्होंने गुजरात के लोगों का जिक्र किया, जिससे काफी विवाद हुआ। खरगे ने कहा था, मोदी जी, आप गुजरात के अनपढ़ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन केरल के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। खरगे की टिप्पणी की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने व्यापक निंदा की थी और आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी के डीएनए में गुजरात विरोधी जहर बहता है और माफी की मांग की। खरगे की टिप्पणी की निंदा करने वाले नेताओं में सीएम भी हैं।



नई दिल्ली (एजेंसी)। मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध को रोकने के लिए, किए गए सीजफायर की घोषणा के पीछे इरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की भूमिका सामने आ रही है। एक्सपर्ट्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस बड़े फैसले के पीछे इरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई थे। जो पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बेटे हैं। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट के अनुसार, अमेरिका और इरान के बीच समझौता कराने के लिए जब पाकिस्तान नेता कई संशोधित प्रस्ताव को इशर उभर करा रहे थे। तब तुर्की और मिस्र खाई पाटने में लगे थे।

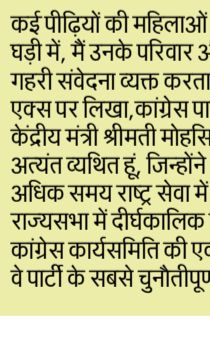
पूर्व केन्द्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का निधन

● राहुल गांधी-मल्लिकार्जुन खरगे ने जताया शोक

नई दिल्ली (एजेंसी)। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मेरठ से तीन बार सांसद रही मोहसिना किदवई का बुधवार को निधन हो गया। 93 साल की उम्र में किदवई ने सुबह चार बजे अस्पताल में आखिरी सांस ली। नोएडा के सेक्टर 40 स्थित आवास से मोहसिना किदवई की अंतिम यात्रा दोपहर 3 बजे निकलेगी। मोहसिन किदवई के निधन पर कई राजनेताओं ने शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी शोक जताया है। राहुल गांधी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है, पूर्व केन्द्रीय मंत्री और पूर्व सांसद मोहसिना किदवई जी के निधन की खबर अत्यंत दुःखद है। वे कांग्रेस पार्टी की एक वरिष्ठ और निष्ठावान नेता थीं, जिनका संपूर्ण जीवन जनसेवा का उदाहरण रहा है। अपनी सादगी, सौम्यता और गरिमामय राजनीतिक सफलता से उन्होंने देश की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। दुःख की इस घड़ी में, मैं उनके परिवार और समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्रीमती मोहसिना किदवई जी के निधन से मैं अत्यंत व्यथित हूँ, जिन्होंने अपने जीवन के छह दशकों से अधिक समय राष्ट्र सेवा में समर्पित किया। लोकसभा और राज्यसभा में दीर्घकालिक सांसद और कई वर्षों तक कांग्रेस कार्यसमिति की एक सम्मानित सदस्य के रूप में, वे पार्टी के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में भी मार्गदर्शक बनीं।



नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से ठीक पहले तुणमूल कांग्रेस और निर्वाचन आयोग (सीईसी) के बीच कड़वाहट अपने चरम पर पहुंच गई है। बुधवार को दिल्ली में चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ और टीएमसी प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई महज सात मिनट की मुलाकात एक बड़े विवाद के साथ समाप्त हुई। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि, चुनाव आयोग की तरफ से भी सफाई दी गई और टीएमसी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। डेरेक ओ ब्रायन ने दावा किया कि जब सबूत सौंपे तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उनसे कहा कि 'दफा हो जाओ'।



नई दिल्ली (एजेंसी)। मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध को रोकने के लिए, किए गए सीजफायर की घोषणा के पीछे इरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की भूमिका सामने आ रही है। एक्सपर्ट्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस बड़े फैसले के पीछे इरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई थे। जो पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बेटे हैं। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट के अनुसार, अमेरिका और इरान के बीच समझौता कराने के लिए जब पाकिस्तान नेता कई संशोधित प्रस्ताव को इशर उभर करा रहे थे। तब तुर्की और मिस्र खाई पाटने में लगे थे।

● रेपो रेट में बदलाव नहीं, महंगे नहीं होंगे लोन

आरबीआई ने ब्याज दर 5.25 फीसदी पर बरकरार रखी

नई दिल्ली (एजेंसी)। नए वित्त वर्ष की पहली मीटिंग में रेपो रेट में बदलाव नहीं किया गया है। इसे 5.25 फीसदी पर बरकरार रखा है। इससे लोन महंगे नहीं होंगे और इएमआई नहीं बढ़ेगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 8 अप्रैल को मॉनैटरी पॉलिसी कमिटी के फैसलों की जानकारी दी। इससे पहले फरवरी में भी रेपो रेट में बदलाव नहीं हुआ था। आरबीआई ने आखिरी बार दिसंबर 2025 में ब्याज दर 0.25 घटाकर 5.25 फीसदी की थी। आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंक इस फायदे को ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। आरबीआई गवर्नर



के मुताबिक, महंगाई में उछाल का खतरा अभी टला नहीं है। खाद्य मौसम और बेमौसम बारिश से महंगाई बढ़ी है।

हर दो महीने में होती है आरबीआई की मीटिंग

मॉनैटरी पॉलिसी कमिटी में 6 सदस्य होते हैं। इनमें से 3 आरबीआई के होते हैं, जबकि बाकी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आरबीआई की मीटिंग हर दो महीने में होती है। वित्त वर्ष 2026-27 में मॉनैटरी पॉलिसी कमिटी की कुल 6 बैठकें होंगी। पहली बैठक 6-8 अप्रैल 2026 को हुई है। आरबीआई जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट कम होने से बैंक को कम ब्याज पर लोन मिलेगा। बैंकों को लोन सस्ता मिलता है, तो वो अवसर इसका फायदा ग्राहकों को पास कर देते हैं।

कोई कोर्ट धार्मिक परंपरा को अंधविश्वास नहीं कह सकता

● सरकार बोली-आप एक्सपर्ट नहीं, यह फैसला विधायिका करेगी

कोर्ट बोला- हमें रिव्यू का पूरा अधिकार, भेदभाव का है मामला

नई दिल्ली (एजेंसी)। धार्मिक स्थलों में महिलाओं के साथ भेदभाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को दूसरे दिन की सुनवाई जारी है। सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- कोई सेक्युलर अदालत किसी धार्मिक प्रथा को सिर्फ अंधविश्वास नहीं कह सकती, क्योंकि उसके पास ऐसा तय करने की विशेषज्ञता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो चीज नगालैंड के किसी समुदाय के लिए धार्मिक हो सकती है, वही मेरे लिए अंधविश्वास लग सकती है। हमारा समाज बहुत विविधतापूर्ण है, यहां

अलग-अलग लोग, धर्म और मान्यताएं हैं। ऐसे में अदालत के लिए ऐसा फैसला देना खतरनाक हो सकता है। इस पर जस्टिस



अमानुल्लाह ने कहा मिस्टर मेहता, आपने बात को बहुत आसान बना दिया है। अदालत के पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट में 50 से ज्यादा रिव्यू पिटीशन

धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव का मामला बीते 26 सालों से देश की अदालतों में है। 2018 में, 5 जजों की बेंच ने 4-1 के बहुमत से मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक हटा दी थी। इसके बाद कई पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गईं। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान बेंच 7 अप्रैल से 22 अप्रैल तक 50 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। कोर्ट में रिव्यू पिटीशनरों और उन्हें सपोर्ट करने वाले 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक दलीलें दे सकेंगे।

अमरीका-ईरान के बीच थम गया युद्ध

● सीजफायर पर ट्रंप की मुहर, मोजतबा ने भी दे दी हरी झंडी ● दो हफ्ते के लिए युद्धविराम, होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा सुनिश्चित



नई दिल्ली (एजेंसी)। मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध को रोकने के लिए, किए गए सीजफायर की घोषणा के पीछे इरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की भूमिका सामने आ रही है। एक्सपर्ट्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस बड़े फैसले के पीछे इरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई थे। जो पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बेटे हैं। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट के अनुसार, अमेरिका और इरान के बीच समझौता कराने के लिए जब पाकिस्तान नेता कई संशोधित प्रस्ताव को इशर उभर करा रहे थे। तब तुर्की और मिस्र खाई पाटने में लगे थे।

इस्लामाबाद में मिलेंगे दोनों देशों के नेता

इसके बाद मंगलवार दोपहर तक, दोनों देशों के बीच आम सहमति बन गई थी। वहीं, कुछ घंटों बाद, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर युद्धविराम समझौते की शर्तें जारी की और दोनों पक्षों से उन्हें स्वीकार करने की अपील की। ट्रंप ने भी फिर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, मैं दो हफ्तों के लिए इरान पर बमबारी और हमले रोकने पर सहमत हूँ।

भारत ने यूएस-ईरान सीजफायर का स्वागत किया

भारत सरकार ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीजफायर का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने 8 अप्रैल को जारी बयान में कहा कि यह कदम पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की दिशा में अहम साबित हो सकता है। बयान में कहा गया कि भारत पहले भी लगातार यह जोर देता रहा है कि तनाव कम करने, संवाद और कूटनीतिक जरिए ही संघर्ष थमेगा।

ईरान से युद्धविराम कर चलते बने ट्रंप, फंस गया इजराइल

अब इजरायल चुकाएगा कीमत, अमेरिका के फैसले से सदमे में नेतन्याहू! तेल अवीव (एजेंसी)। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्धविराम कर जंग से बाहर निकल आए हैं जबकि सहयोगी इजरायल युद्ध के मैदान से उन्हें हारान परेशान देख रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जीत का हिलोरा पीट दिया है जबकि हकीकत ये है कि ईरान ने अमेरिका की एक भी शर्त नहीं मानी। उल्टा होर्मुज स्ट्रेट पर अब तेहरान का कंट्रोल भी हो चुका है। इजरायल में सदमा है। विपक्षी नेता ने नेतन्याहू पर नाकामी के आरोप लगाए हैं। इजरायली अखबार देश की सरकार से कठिन सवाल पूछ रहे हैं। अखबारों में पूछा गया है कि क्या वाकई ईरान होर्मुज स्ट्रेट खोल रहा है? क्योंकि इरान ने तो आधिकारिक बयान में जहाजों के गुजरने के लिए शर्तें लगा दी हैं। बिना ईरान सेना की इजाजत के कोई भी जहाज होर्मुज से निकल नहीं सकते। युद्धविराम होने के बाद भी ईरान की तरफ से मध्य इजरायल पर मिसाइलों की बौछार की गई। इजरायल की डेडलिजेंस कम्पैनिटी को पहले से ही अंदाजा था कि अगर सीजफायर होता है तो इस तरह के हमले हो सकते हैं। ईरान और उसके प्रांतीय संगठन संदेश दे रहे हैं कि वो जीत चुके हैं और इजरायल में सवाल पूछा जा रहा है।



चिल्लाने लगे डेरेक ब्रायन, सीईसी ने कहा-यहां से दफा हो जाओ

● बंगाल चुनाव के बीच महासंग्राम, टीएमसी के गंभीर आरोप

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से ठीक पहले तुणमूल कांग्रेस और निर्वाचन आयोग (सीईसी) के बीच कड़वाहट अपने चरम पर पहुंच गई है। बुधवार को दिल्ली में चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ और टीएमसी प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई महज सात मिनट की मुलाकात एक बड़े विवाद के साथ समाप्त हुई। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि, चुनाव आयोग की तरफ से भी सफाई दी गई और टीएमसी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। डेरेक ओ ब्रायन ने दावा किया कि जब सबूत सौंपे तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उनसे कहा कि 'दफा हो जाओ'।



नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से ठीक पहले तुणमूल कांग्रेस और निर्वाचन आयोग (सीईसी) के बीच कड़वाहट अपने चरम पर पहुंच गई है। बुधवार को दिल्ली में चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ और टीएमसी प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई महज सात मिनट की मुलाकात एक बड़े विवाद के साथ समाप्त हुई। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि, चुनाव आयोग की तरफ से भी सफाई दी गई और टीएमसी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। डेरेक ओ ब्रायन ने दावा किया कि जब सबूत सौंपे तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उनसे कहा कि 'दफा हो जाओ'।

जम्मू-कश्मीर में आतंक के खिलाफ एलजी का ऐवशन जारी

● लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े दो सरकारी कर्मचारी बर्खास्त

जम्मू (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी लगातार जारी है। एलजी मनोज सिन्हा ने बुधवार को दो सरकारी कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी है। इनमें से फरहत अली खांडे नाम का एक कर्मचारी यामबन में शिक्षा विभाग में क्लास 2 का कर्मचारी था। वहीं दूसरा कर्मचारी ग्रामीण विकास विभाग में क्लास-2 का कर्मचारी था, जिसकी पहचान बांदीपोरा के रहने वाले मोहम्मद शफी डार के रूप में हुई है। ये बर्खास्तगी भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2)(ए) के तहत की गई है।



होर्मुज में फंसे 16 जहाजों को लाने की तैयारी शुरू

● सीजफायर के तुरंत बाद भारत ने ईरान से साधा संपर्क ● क्षेत्रीय शांति और ऊर्जा सुरक्षा भारत की है प्राथमिकता



नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम एशिया में ईरान-अमेरिका के बीच घोषित सीजफायर की घोषणा के तुरंत बाद बुधवार को भारत ने ईरान से संपर्क साधा है ताकि होर्मुज के पश्चिम में उसके जो तेल व गैस के जहाज फंसे हैं उन्हें तुरंत वहां से स्वदेश लाया जा सके। भारत सरकार ने सीजफायर का स्वागत करते हुए आशा जताई है कि इससे क्षेत्र में स्थायी शांति कायम होगा। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है, हम घोषित युद्ध विराम का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की ओर ले जाएगा। जैसा कि हम पहले से लगातार वकालत कर रहे थे, संघर्ष को कम करने के साथ संवाद और कूटनीति ही चल रहे संघर्ष को जल्द समाप्त करने के लिए आवश्यक हैं। भारत ने आगे कहा है कि संघर्ष से पहले ही लोगों को अपार पीड़ा पहुंची है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क बाधित हुए हैं।

कम होगा ऊर्जा संकट, सरकार ने जताया विश्वास

सरकारी सूत्रों के अनुसार, सीजफायर की घोषणा के बाद भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर जारी चिंता अब कम होने की उम्मीद है। वर्तमान में भारत के 16 जहाज होर्मुज के पश्चिमी हिस्से में फंसे हुए हैं। इयम में अधिकांश तेल और गैस से जुड़े जहाज हैं। इन जहाजों में तकरीबन दो लाख टन से ज्यादा एलपीजी है जिसकी भारत को सख्त जरूरत है। इन जहाजों को तुरंत निकालने के लिए भारतीय सरकार ईरान के साथ लगातार संपर्क में है। भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत आयात करता है, जिसमें पश्चिम एशिया से आने वाला हिस्सा करीब 60 प्रतिशत है।

दक्षिण के रण में मोदी की हुंकार, राहुल गांधी गायब!



चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु में चुनावी सरगमियां जोरों पर हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राज्य के दौरे कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तमिलनाडु में चुनाव प्रचार से दूरी राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर रही है। पिछले दो महीनों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा और अपने सहयोगी दलों

● चुनाव से पहले ही दरक रहा कांग्रेस-डीएमके गठबंधन

के पक्ष में माहौल बनाने के लिए तीन बार तमिलनाडु का दौरा किया है। उनका यह अभियान यहीं नहीं रुकने वाला है; पीएम मोदी 15 अप्रैल को फिर से राज्य का दौरा करने वाले हैं, जहां वे नागरकोइल में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित कर वोट मांगेंगे। पीएम मोदी के इस ताबड़तोड़ प्रचार के ठीक विपरीत, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब तक तमिलनाडु में एक बार भी चुनाव प्रचार नहीं किया है। उनकी इस अनुपस्थिति ने इन अटकलों को हवा दे दी है कि कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कडगम गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राजनीतिक विश्लेषक इस स्थिति की तुलना 2021 के विधानसभा चुनाव से कर रहे हैं। उस समय राहुल गांधी ने चुनाव से काफी पहले, जनवरी महीने में ही तीन दिवसीय दौरे



के साथ तमिलनाडु में अपने चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया था।

सीट बंटवारे की खींचतान का नतीजा

डीएमके के एक पदाधिकारी ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहा, राहुल ने अपने भाषण में एक बार भी स्टालिन के नाम का जिक्र नहीं किया। इसके जवाब में स्टालिन ने भी राहुल गांधी के बारे में कोई बात नहीं की। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दोनों नेताओं के बीच यह दूरी दरअसल चुनाव से पहले सीट-बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों के बीच हुई खींचतान और मनमुटाव का सीधा नतीजा है। डीएमके सूत्रों की मानें तो उनकी तरफ से राहुल और स्टालिन की मुलाकात कराने की कोई कोशिश भी नहीं की गई थी।

पार्टियों की सफाई और आगामी योजना

गठबंधन में अनबन की इन खबरों के बीच, डीएमके के संगठनात्मक सचिव आरएस भारती ने सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों ने अपनी-अपनी जनसभाओं की योजना बहुत पहले ही बना ली थी और आखिरी समय में एक संयुक्त रैली आयोजित करने के लिए शंभुल्लस में बदलाव प्रचार करते नजर आएंगे। इस बीच, उन्होंने यह दावा जरूर किया कि दोनों नेता जल्द ही एक साथ चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। इस बीच, राज्य के कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि राहुल गांधी के चुनाव प्रचार का कार्यक्रम अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है।

जनादेश 2026- विधानसभा चुनावों में लोकतंत्र की अग्निपरीक्षा और सत्ता के नए समीकरण

(लेखक - योगेश कुमार गोयल)

- सियासी रण में पांच राज्य- सत्ता की कुर्सी किसके नाम ?

दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल की राजनीति अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का प्रभाव इतना गहरा है कि राष्ट्रीय दलों की भूमिका सीमित हो जाती है। 234 सीटों वाली विधानसभा में 5.67 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे। पिछले चुनाव में डीएमके गठबंधन ने सत्ता हासिल की थी और इस बार भी वह अपने 'द्रविड़ मॉडल', सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं के दम पर मैदान में है। वहीं एआईएडीएमके गठबंधन महंगाई, बिजली संकट और स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोल रहा है।

पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों ने देश की राजनीति को उबाल पर ला दिया है। केरल से लेकर असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी तक सियासी हलचल अपने चरम पर है। रैलियों की गुंज, वादों की बरसात और आरोप-प्रत्यारोप के तीखे तीरों के बीच लोकतंत्र का यह उत्सव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। हर राजनीतिक दल अपने-अपने एजेंडे, घोषणापत्र और रणनीति के साथ मैदान में है और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है। इस बार का चुनाव केवल सरकार बनाने का साधन नहीं बल्कि बीते पांच वर्षों के कामकाज का जनमत संग्रह और आने वाले राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करने वाला निर्णायक क्षण है।

इन पांच राज्यों की कुल 824 विधानसभा सीटों पर लगभग 17.4 करोड़ मतदाता अपने मतधिकार का प्रयोग करेंगे। यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि 116 लोकसभा सीटों के प्रभाव क्षेत्र से जुड़ा हुआ वह राजनीतिक रणक्षेत्र है, जो राष्ट्रीय राजनीति की धुरी को प्रभावित कर सकता है। चुनाव कार्यक्रम भी बेहद दिलचस्प है, असम, केरल और पुदुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान होगा, तमिलनाडु में 23 अप्रैल को और पश्चिम बंगाल में दो चरणों (23 और 29 अप्रैल) में वोट डाले जाएंगे। नतीजे 4 मई को घोषित होंगे और उसी दिन यह स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने किसके पक्ष में अपना विश्वास व्यक्त किया। इस बार का चुनावी

परिदृश्य कई स्तरों पर जटिल और बहुआयामी है। सत्ताधारी दल जहां अपने विकास कार्यों, कल्याणकारी योजनाओं और 'उबल इंजन' जैसे नारों के सहारे जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक असमानता और प्रशासनिक खामियों को मुद्दा बनाकर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। यह संघर्ष अब केवल सत्ता का नहीं रहा बल्कि विचारधारा, नीतियों और विकास के मॉडलों की प्रतिस्पर्धा में बदल चुका है।

सबसे अधिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है पश्चिम बंगाल, जहां राजनीतिक तापमान सबसे ज्यादा है। 294 सीटों वाली विधानसभा में 6.44 करोड़ मतदाता अपने मतधिकार का उपयोग करेंगे। पिछले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत हासिल कर सत्ता पर कब्जा बनाए रखा था जबकि भाजपा ने मुख्य विपक्षी दल के रूप में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी। इस बार मुकाबला और अधिक तीखा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस अपने 'बंगाल मॉडल', महिला सशक्तिकरण योजनाओं और क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दों के साथ मैदान में है, वहीं भाजपा 'डबल इंजन' सरकार के वादे और घुसपैठ जैसे मुद्दों को प्रमुखता दे रही है। रोजगार, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे मुद्दे भी चुनावी विमर्श के केंद्र में हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यहां मुकाबला बेहद कांटे का होगा, एक तरफ ममता बनर्जी की राजनीतिक विरासत दांव पर है तो दूसरी ओर भाजपा के लिए यह पूर्वी भारत में विस्तार का सुनहरा अवसर है।

असम का चुनाव भी कम दिलचस्प नहीं है। 126 सीटों वाली विधानसभा में 2.25 करोड़ मतदाता निर्णायक भूमिका निभाएंगे। यहां मुख्य

सवाल यही है कि क्या भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर पाएगी या कांग्रेस और उसके सहयोगी दल वापसी का रास्ता तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में भाजपा विकास, बुनियादी ढांचे और सुरक्षा के मुद्दों को लेकर जनता के बीच है। वहीं विपक्ष सीएफ-एनआरसी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय पहचान जैसे मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की सक्रियता ने इस चुनाव को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। असम में परिणाम न केवल राज्य की राजनीति बल्कि पूर्वोत्तर भारत में शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करेंगे।

दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल की राजनीति अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का प्रभाव इतना गहरा है कि राष्ट्रीय दलों की भूमिका सीमित हो जाती है। 234 सीटों वाली विधानसभा में 5.67 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे। पिछले चुनाव में डीएमके गठबंधन ने सत्ता हासिल की थी और इस बार भी वह अपने 'द्रविड़ मॉडल', सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं के दम पर मैदान में है। वहीं एआईएडीएमके गठबंधन महंगाई, बिजली संकट और स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोल रहा है। इसके अलावा अभिनेता विजय की पार्टी का चुनावी मैदान में उतरना एक नया समीकरण बना सकत है, खासकर युवा मतदाताओं के बीच।

केरल में 140 सीटों के लिए 2.7 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे। यहां का चुनाव पारंपरिक रूप से सत्ता परिवर्तन के लिए जाना जाता रहा है लेकिन पिछले चुनाव में वाम मोर्चे ने लगातार दूसरी

बार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया था। इस बार यदि वह तीसरी बार सत्ता में आता है तो यह एक नया राजनीतिक अध्याय होगा। वाम मोर्चा अपने स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के मॉडल को प्रमुखता दे रहा है जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर हमलावर है। भाजपा भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय होता जा रहा है।

पुदुचेरी भले ही छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो, लेकिन यहीं की राजनीति बेहद संवेदनशील और निर्णायक है। 30 सीटों वाली विधानसभा में 9.44 लाख मतदाता मतदान करेंगे। यहां गठबंधन राजनीति का महत्व सबसे अधिक है, जहां छोटे-छोटे वोट अंतर भी सत्ता की दिशा तय कर सकते हैं। पिछले चुनाव में एनडीए गठबंधन ने सत्ता हासिल की थी और इस बार भी वह अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस और क्षेत्रीय दल सत्ता वापसी के लिए संघर्षरत हैं। इन सभी राज्यों में एक समान बात यह है कि वोट प्रतिशत और सीटों का समीकरण हमेशा सीधा नहीं होता। कई बार मामूली वोट अंतर भी भारी सीट अंतर में बदल जाता है। यही कारण है कि राजनीतिक दल बूथ स्तर तक अपनी रणनीति को मजबूत कर रहे हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार ने चुनावी अभियान को एक नई दिशा दी है, जहां नैरेटिव की लड़ाई केवल मैदान में नहीं बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लड़ी जा रही है।

चुनावी मुद्दों की बात करें तो इस बार कोई एक रुढ़ हावी नहीं है। रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि संकट और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दे अलग-अलग दिशाओं में सक्रिय विरिष्ठ

रूप में सामने आ रहे हैं। यही विविधता इन चुनावों को और अधिक जटिल और रोचक बनाती है। राजनीतिक दृष्टि से इन चुनावों को 2029 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। इन राज्यों से आने वाली 116 लोकसभा सीटें राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। यदि भाजपा असम में अपनी पकड़ बनाए रखती है, पश्चिम बंगाल में बेहतर प्रदर्शन करती है और दक्षिण भारत में अपनी उपस्थिति मजबूत करती है, तो उसकी राष्ट्रीय स्थिति और सुदृढ़ हो सकती है। वहीं उर्जा लेकर आएगी जबकि तमिलनाडु में डीएमके की निरंतरता द्रविड़ राजनीति की दिशा तय करेगी।

कुल मिलाकर, यह चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला नहीं बल्कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा है। मतदाता इस बार खामोश जरूर हैं लेकिन उनकी चुप्पी के भीतर गहराई से सोच-विचार और निर्णय की प्रक्रिया चल रही है। 4 मई को जब परिणाम सामने आएंगे, तभी यह स्पष्ट होगा कि किसने जनता की अपेक्षाओं को समझा और किसे आत्ममंथन की आवश्यकता है। लोकतंत्र का यह महापर्व एक बार फिर यह सिद्ध करने का रहा है कि अंतिम निर्णय जनता के हाथ में होता है और वही निर्णय देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करता है।

(लेखक 36 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय विरिष्ठ पत्रकार और 'सागर से अंतरिक्ष तक- भारत की राह क्रांति' सहित कई पुस्तकों के लेखक हैं)

कब पुनः शुरू होगी वरिष्ठ नागरिकों की रेल यात्रा छूट?

(लेखिका- निर्मल रानी)

मार्च 2020 में कोरोना महामारी के दौरान दुनिया के अनेक देशों में तरह तरह के अभूतपूर्व फ़ैसले लिये गये थे। प्रायः ऐसे फ़ैसलों का मक़सद कोरोना महामारी के सं मण को यथार्थसंभव रोकना था। इसी दौरान पूरे विश्व में हवाई यातायात तक ठप्प हो गया। अनेक देशों में लॉक डाउन लगा दिया गया था। कल-कारखाने सभी प्रकार के यातायात, व्यवसाय, उद्योग बाज़ार आदि सभी बंद कर दिये गये थे। भारत भी उन्हीं देशों में एक था जहाँ पूर्ण लॉक डाउन लगा दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं 24 मार्च 2020 की रात को पहले चरण के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की। 25 मार्च 2020 की मध्यरात्रि से लागू हुआ प्रथम चरण का यह पूर्ण लॉकडाउन पहले तो केवल 21 दिनों का बताया गया था परन्तु बाद में भी इसे कई चरणों में आगे बढ़ाया गया था। इसी पूर्ण लॉकडाउन के दौरान रेल सहित देश की सभी यातायात सुविधाओं को पूर्णतः स्थगित कर दिया गया था। कोरोना का प्रभाव कम होने के बाद भारतीय रेलवे ने 12 मई से चरणबद्ध तरीके से यात्री ट्रेनों को फिर से शुरू करने की योजना बनाई थी। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम 15 विशेष ट्रेनों के द्वारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को असम, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू, झारखंड,कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा के प्रमुख शहरों से जोड़ा गया था। बाद में धीरे धीरे इनका विस्तार किया गया।

भारत सरकार ने इस अवसर का लाभ उठाते हुये वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा में रेल टिकट पर मिलने वाली आंशिक छूट को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को समाप्त करते समय सरकार द्वारा यह तर्क दिया गया था कि 'अनावश्यक यात्रा रोकने' के लिये यह छूट समाप्त की गयी है। परन्तु आज पूरे छः वर्ष बीत जाने के बाद भी जबकि देश भर में ट्रेन सेवाएं लगभग सामान्य हो चुकी हैं, यह छूट आज तक बहाल नहीं हुई है।

गौरतलब है कि उसी दौरान प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि इतनी बड़ी आपदा, भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। भारत ने आपदा को, अवसर में बदल दिया है। रेल विभाग ने भी इसी आपदा में अवसर देखते हुये कोरोना काल की आड़ में कई ऐसे निर्णय ले डाले जो सरकार के लिये भले ही लाभदायक रहे हों परन्तु रेल यात्रियों के लिये तो हर्षिण्ड नहीं थे। मिसाल के तौर पर अनेक पैसेंजर ट्रेन को एक्सप्रेस ट्रेन बनाकर कहीं स्टॉपिज कम कर दिया गये तो कहीं किराया बढ़ा दिया गया। कई ट्रेन स्थाई रूप से कैंसिल कर दी गयी तो कई ट्रेन के रुट बदल दिये गये। इनमें से कोरोना काल के समय किये गये कुछ परिवर्तन तो यथार्थवत् किये गये परन्तु कुछ कोरोना काल समाप्त होने के बावजूद आज तक वैसे ही हैं। जैसे कि कोरोना काल में वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा में रेल टिकट पर मिलने वाली आंशिक छूट को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना।

सवाल यह है कि जब यह छूट समाप्त करते समय 'अनावश्यक यात्रा रोकने' जैसा तर्क दिया गया था तो आज तक उस छूट को पुनः लागू क्यों नहीं किया गया ? जबकि अब न केवल कोरोना काल के पूर्व की लगभग सभी ट्रेन्स चल रही हैं बल्कि अनेक नई ट्रेन्स भी पटरियों पर दौड़ने लगी हैं? गौरतलब है कि भारतीय रेल ने छत्र, दिव्यांगजन, रोगी, स्वतंत्रता सेनानी, युद्ध विधवाएं जैसी कुल 53 श्रेणियों में विभिन्न स्तर पर छूट दी थी। इन्हीं में वरिष्ठ नागरिक भी शामिल थे। वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली टिकट छूट की सुविधा विभिन्न चरणों में 1985 में शुरू की गई थी। अगस्त 2001 से इसे स्वीच्छक बना दिया गया अर्थात् वरिष्ठ नागरिक चाहें तो छूट ले सकते थे। लेकिन यात्रा के दौरान छूट लेने वालों को अपनी आयु का कोई न कोई प्रमाण जैसे आधार, पैन कार्ड या पासपोर्ट आदि यात्रा के समय अपने साथ रखना अनिवार्य कर दिया गया था। इस सुविधा का लाभ देश के बुजुर्गों ने 35 वर्षों तक उठाया परन्तु स्वयं को लोकहितकारी बताने का ढिंढोरा पीटने वाली मोदी सरकार ने इसे कोरोना की आड़

में समाप्त कर दिया। जो सरकार छूट समाप्त करते समय 'अनावश्यक यात्रा रोकने' जैसा तर्क दे रही थी वहीं सरकार अब इसे सरकार पर 'वित्तीय बोझ' मान रही है। सरकार का तर्क है कि रेलवे पहले से ही भारी घाटे में चल रही है। रेल मंत्री संसद में बता भी चुके हैं कि रेलवे सभी यात्रियों को औसतन 45व सस्मिडी दे रही है। गोया प्रत्येक यात्री को पहले से ही काफी राहत मिल रही है। कुछ आंकड़े बताते हैं कि सरकार अनावश्यक यात्रा रोकने जैसे उपाय कर देश के बुजुर्गों से अब तक दस हजार करोड़ से अधिक रुपये कमा चुकी है।

इसी सन्दर्भ में इस बात का जि' करना भी जरूरी है कि बुजुर्गों की रेल यात्रा छूट समाप्त करने वाली यही सरकार जब चाहती है और जहाँ से चाहती है विभिन्न तीर्थ स्थलों की मुफ्त यात्रा हेतु विशेष ट्रेन चला देती है। जब चाहती है चुनावी राज्यों के लिये स्थानीय प्रवासियों हेतु विशेष ट्रेन चलाकर उन्हें मतदान करने हेतु निःशुल्क भेजती है। गोया अपने वोट बैंक साधने के लिये तो सरकार तत्पर रहती है परन्तु इसी सरकार के पास न तो कोरोना काल की शुरुआत में इन्हीं प्रवासी मजदूरों को उनके राज्यों व गहरी निराशा से भेजने के लिये कोई ट्रेन थी न ही आज उन ट्रेन्स पर चलने वाले बुजुर्गों के लिये पूर्व में मिलने वाली छूट ? हालाँकि कभी कभार अपुष्ट सूत्रों से यह खबर सुनाई देती है कि शायद सरकार पुनः यह छूट देने पर विचार कर रही है। परन्तु इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। विश्वी सांसदों ने इसे 'बुजुर्गों के साथ अन्याय' बताते हुये लोकसभा में भी कई बार सवाल उठाए परन्तु सत्ता पक्ष ने 'वित्तीय कारण' देकर यह सुविधा शुरू करने से इनकार कर दिया। बुजुर्ग संगठनों में भी इसे लेकर काफी नाराजगी व गहरी निराशा है। इसी लिये देश यह सवाल कर रहा है कि जब सांसदों विधायकों को आजीवन पेंशन देने के लिये 'वित्तीय कारण' आड़े नहीं आते तो आखिर सरकार बुजुर्गों को ट्रेन में छूट क्यों नहीं दे रही? वरिष्ठ नागरिकों को आज भी इस बात की आस है कि आखिर रेल यात्रा में मिलने वाली छूट कब शुरू होगी?

ईश्वर का आहार है साधना

तुमने ईश्वर को सदैव पिता के रूप में देखा है, कहीं ऊपर स्वर्ग में। मन में बैठी इस धारणा के संग तुम ईश्वर से कुछ मांगना चाहते हो और उनसे कुछ लेना। परन्तु क्या तुम ईश्वर को एक शिशु के रूप में देख सकते हो? जब तुम ईश्वर को शिशु के रूप में देखते हो तो तुम्हारी कोई मांग नहीं होती। ईश्वर तो तुम्हारे अस्तित्व का अन्तःकरण है। तुम ईश्वर को धारण किये हो। तुम्हें अपने गर्भ का ध्यान रखना है और इस शिशु को संसार में जन्म देना है। ईश्वर तुम्हारा शिशु है। वे तुमसे बच्चे की तरह चिपककर रहते हैं जब तक तुम वृद्ध होकर मर नहीं जाते। ईश्वर पोषण के लिए पुकारते रहते हैं। संसार में उनके पोषण के लिए उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। साधना, सत्सग और सेवा ईश्वर के पोषक आहार हैं। तुम ऐसा क्या सोचते हो कि ईश्वर एक ही हैं? ईश्वर भी अनेक क्यों नहीं हो सकते? यदि ईश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि के अनुसार बनाया है, तो उनकी छवि क्या है? अप्रीकी, मंगोलियन, कॉकिसियन, जापानी या फिलिपिनो? मनुष्य इतने प्रकार के क्यों हैं, वस्तुओं की इतनी विविधताएं क्यों हैं? वृक्ष सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता। सांप बादल, मच्छर या

सब्जी सिर्फ एक प्रकार के नहीं। कुछ भी सिर्फ एक प्रकार का नहीं है, तो फिर केवल ईश्वर को ही एक क्यों होना चाहिए?

जिस चेतना ने इस सम्पूर्ण सृष्टि की रचना की है और जो विविधता की प्रेमी है, वह चेतना नीरस कैसे हो सकती है? ईश्वर को विविधता पसंद है, तो वे भी अवश्य ही वैविध्य होंगे। ईश्वर अनेक नाम, रूप और प्रकार से अभिव्यक्त होते हैं। कुछ विचारधारा का व्यक्त ईश्वर को उनके विभिन्न रूपों में प्रकट होने की स्वतंत्रता नहीं देते। वे उन्हें एक ही रूप-वर्दी में चाहते हैं। अवसर के अनुसार जब तुम अपने रूप को बदलते हो तो कैसे सोच सकते हो कि चेतना में कोई विविधता न हो?

हमारे पूर्वज इस बात को समझते थे और इसीलिए उन्होंने दिव्यता के अनंत गुण व रूपों का ज्ञान कराया। चेतना नीरस और उबाऊ नहीं है। जो चेतना इस सृष्टि का आधार है, वह गतिमान और परिवर्तनशील है। ईश्वर एक ही नहीं, अनेक है। जब तुम दिव्यता की विविधता स्वीकारते हो, तब तुम कष्ट और रूढ़िवादी नहीं रह जाते।

विचार मंथन

शर्तों के साथ ईरान और अमेरिका के बीच 15 दिन का सीज फायर

(लेखक - सनत जैन)

ईरान और अमेरिका के बीच दो सप्ताह के लिए युद्ध विराम के लिए सहमति बन गई है। अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया। ईरान ने भी अधिकृत रूप से इसकी घोषणा की। सीज फायर के बाद हमले तत्काल रूप से बंद हो गए हैं। ईरान ने इसके लिए अधिकृत रूप से आदेश जारी किए हैं। युद्ध विराम को लेकर 10 शर्तों के साथ ईरान ने प्रस्ताव पेश किया है। चीन द्वारा दोनों पक्षों को समझाइस दिए जाने के बाद 15 दिन के लिए युद्ध विराम घोषित किया गया है। इसकी घोषणा होती ही, इसके सकारात्मक परिणाम भारत सहित दुनिया के सभी देशों में देखने को मिले हैं। एक नई आशा की किरण जागी है। दोनों पक्ष गंभीरता के साथ विचार

करके स्थाई रूप से युद्ध रोकने और शांति के लिए प्रयास करेंगे। इसके लिए दोनों पक्षों का एक मंच पर आना जरूरी था। पाकिस्तान ने तीनों पक्षों के बीच बातचीत के लिये जो प्रयास किया, वह सार्थक हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इस फैसले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख असीम मुनीर का उल्लेख किया।

डोनाल्ड ट्रंप ने यह उल्लेख किया है, ईरान को स्टेट आफ हार्मोज को फिर से खोलना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, अमेरिका ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अमेरिका अब तेहरान के साथ निर्णायक फैसले की स्थिति में आ गया है। अब जो भी समझौता होगा वह दीर्घकालिक शांति के लिए होगा। ईरान की ओर से शीर्ष अधिकारी बातचीत करने के लिए

पाकिस्तान आएंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति इस बातचीत में शामिल होंगे। इस फैसले के आते ही सारी दुनिया के देशों ने राहत की सांस ली है। ऊर्जा संबंधी संकटों और युद्ध को लेकर जो स्थिति बनी हुई थी। उससे सारी दुनिया को अस्थायी रूप से राहत मिली है। भारत में इसका बड़ा असर देखने को मिला। शेंयर बाजार ने 2800 अंकों की छलांग लगाई। तक वह इस तरह की कार्रवाई राष्ट्रपति कर सकते थे। इसके पहले उन्हें संसद की अनुमति लेना अनिवार्य था। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप के पास अन्य कोई विकल्प नहीं था। एक महीने से अधिक युद्ध चलते हुए हो गए थे। युद्ध में ईरान के साथ-साथ इजराइल को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जिन खाड़ी के देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे थे, ईरान ने लगभग सभी में ध्वस्त

इसके तुरंत बाद ईरान पर हमला किया गया। इससे सारी दुनिया के देश अमेरिका से नाराज थे। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का विरोध शुरू हो गया है।

अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस की मंजूरी लिए बिना जिस तरह से ईरान पर हमला किया था। अमेरिकी कानून के अनुसार केवल 45 दिन तक वह इस तरह की कार्रवाई राष्ट्रपति कर सकते थे। इसके पहले उन्हें संसद की अनुमति लेना अनिवार्य था। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप के पास अन्य कोई विकल्प नहीं था। एक महीने से अधिक युद्ध चलते हुए हो गए थे। युद्ध में ईरान के साथ-साथ इजराइल को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जिन खाड़ी के देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे थे, ईरान ने लगभग सभी में ध्वस्त

कर दिये हैं। अमेरिका की जो साख दुनिया में बनी हुई थी, इस युद्ध में वह लगभग खत्म हो गई है। ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप जल्द से जल्द युद्ध से बाहर निकलना चाहते थे। इसमें पाकिस्तान ने पहल की। चीन ने अपनी सामरिक और आर्थिक शक्ति का एहसास कराकर अमेरिका और ईरान दोनों को एक मंच पर लाने का जो काम किया है। युद्ध विराम से सारे विश्व को राहत मिली है। अमेरिका और ईरान के इस युद्ध में सबसे ज्यादा भूमिका इजरायल की थी। ग्रेटर इजरायल के प्रतिकल्पना पर काम कर रहे इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और मोसाद द्वारा जो अमेरिका को जो जानकारी दी गई थी, वह सही नहीं थी।

अति उत्साह में डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में कूद गए। जिसके कारण अब उन्हें राष्ट्रपति पद को

बचा पाना मुश्किल दिख रहा है। इसके अलावा अमेरिका में नवंबर माह में जो चुनाव होने हैं। उसको लेकर उन्हें अपनी पार्टी से चुनौती मिलने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप का स्वभाव है वह आक्रामक होकर अपनी विपक्षी के ऊपर हमला करते हैं। पिछले 1 साल में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में एक्सपोज हुए हैं। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति की जो छवि बनी थी, उसमें बहुत बड़ा बड़ा लग गया है। अमेरिका को सारी दुनिया के देशों से कई तरह की चुनौतियां मिलना शुरू हो गई हैं। डॉलर मुद्रा को चुनौती मिल रही है। नाटो और यूरोपीय देशों ने अमेरिका का साथ एक तरह से छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में ईरान से ज्यादा अमेरिका को युद्ध विराम की जरूरत थी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इसमें सबसे बड़ी बाधा बने हुए थे।

शेयर बाजार बंपर उछाल के साथ बंद

संसेक्स 2,946.32 , निफ्टी 873 अंक उछला निवेशकों को 17 लाख करोड़ रुपए का फायदा

मुंबई ।

भारतीय शेयर बाजार में बुधवार के भारी तेजी रही। अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम के बाद दुनिया भर से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही खरीदारी हावी होने से बाजार में ये बंपर तेजी आई। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई संसेक्स 2,946.32 अंक के उछाल के साथ ही 77,563.90 और 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 873.70 अंक बढ़कर 23,997.35 पर बंद हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष थमने के बाद बाजार में

चौतरफा तेजी रही। रियल्टी और ऑटो स्टॉक्स में आज भारी तेजी रही। निफ्टी रियल्टी, और निफ्टी ऑटो की मजबूती के साथ सबसे अधिक लाभ में रहे। निफ्टी निजी बैंक , निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेस , निफ्टी पीएसयू बैंक , निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और निफ्टी इन्फ्रा बढ़त के साथ बंद हुआ। एक भी सूचकांक में गिरावट नहीं रही। आज लार्जकैप के साथ-साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी तेजी रही। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 2,198.95 अंक की बढ़त के साथ 56,799.50 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 694.75 अंक की बढ़त के साथ

16,538.05 पर पहुंचा। संसेक्स पैक में इंडिगो, एलएंडटी, बजाज फाइनेंस, एमएंडएम, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाइटन, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक, अदाणी पोर्ट्स, आईसीआईसीआई बैंक, इटरनल, कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेट्रोल, टाटा स्टील और एसबीआई के शेयर लाभ में रह जबकि टेक महिंद्रा, सन फार्मा और पावर ग्रिड में गिरावट रही। बाजार में तेजी के कारण कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 17 लाख करोड़ रुपए बढ़कर करीब 446 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पहले 429 लाख करोड़

रुपए था। बाजार जानकारों के अनुसार युद्ध विराम की घोषणा के बाद कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आई है और ब्रेंट क्रूड का दाम करीब 14 फीसदी नीचे आकर 94 डॉलर प्रति बैरल पहुंचा। इसी प्रकार आज सुबह बाजार की तेज शुरुआत हुई। शुरुआती कारोबार में संसेक्स और निफ्टी में 3 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की गई, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत होता नजर आया। वैश्विक स्तर पर सकारात्मक माहौल और एशियाई बाजारों में मजबूती का असर भारतीय बाजार पर साफ दिखाई दिया। संसेक्स 3



फीसदी से अधिक उछलकर 77,000 के पार खुला। वहीं निफ्टी भी तेजी के साथ 23,800 के ऊपर पहुंच गया।

हुंटे मोटर इंडिया मई से वाहनों की कीमतें बढ़ाएगी

नई दिल्ली ।

वाहन विनिर्माता कंपनी हुंटे मोटर इंडिया लिमिटेड ने बढ़ती लागत के कारण मई से अपने वाहनों की कीमतों में एक प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने की बुधवार को जानकारी दी। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि उसने मई 2026 से अपने सभी मॉडल की कीमतों में एक प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने की योजना बनाई है। यह मूल्य संशोधन विभिन्न लागतों में वृद्धि के कारण किया जा रहा है। हुंटे मोटर इंडिया ने कहा कि कीमतों में बढ़ोतरी विभिन्न मॉडल एवं संस्करण के आधार पर अलग-अलग होगी। कंपनी ने कहा कि हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि बढ़ती लागत को खुद वहन कर ग्राहकों को कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाया जाए। हालांकि, कच्चे तेल की लागत में लगातार वृद्धि से इसका एक हिस्सा मामूली मूल्य वृद्धि के रूप में ग्राहकों पर डालना जरूरी हो गया है।

यूएस-ईरान युद्धविराम और आरबीआई की नीति से बॉन्ड प्रतिफल में गिरावट

बॉन्ड प्रतिफल 0.12 प्रतिशत घटकर सात प्रतिशत से नीचे आया



मुंबई ।

अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के सशर्त युद्धविराम और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के रेपो दर को 5.25 फीसदी पर यथावत रखने के फैसले से बुधवार को भारत के बॉन्ड बाजार में रहत देखने को मिली। इस फैसले के बाद 10-वर्षीय मानक बॉन्ड का प्रतिफल 7 प्रतिशत से नीचे आ गया जो निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत है। भारतीय समाशोधन निगम के अनुसार, सुबह के कारोबार में 10-वर्षीय बॉन्ड का प्रतिफल 7.04 फीसदी से घटकर 6.92 फीसदी पर आ गया। पश्चिम एशिया में युद्धविराम के बाद बॉन्ड बाजार की धारणा बेहतर हुई, जिससे निवेशकों ने बिकवाली कम की। युद्धविराम के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 94.94 डॉलर प्रति बैरल पर बनी, जो कुछ दिन पहले 100 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गई थी। इससे भारत जैसे तेल आयातक देशों में आयातित मुद्रास्फीति का दबाव कम हुआ। अप्रैल में आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर 5.25 फीसदी पर स्थिर रखने से बॉन्ड प्रतिफल को अतिरिक्त समर्थन मिला। नीति निर्णय ऐसे समय आया है जब करीब 40 दिन से पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई थी और बॉन्ड प्रतिफल बढ़कर 7 फीसदी से ऊपर चला गया था।

वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर का मिलाजुला प्रदर्शन

वेस्ट एशिया संकट और महंगे कच्चे तेल ने बढ़ाई चुनौतियां



नई दिल्ली ।

वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर का प्रदर्शन मिला-जुला रहा। शुरुआती महीनों में मांग मजबूत थी, लेकिन मार्च के अंत में वैश्विक और मौसमी कारकों ने स्थिति को प्रभावित किया। बाजार के जानकारों के मुताबिक इस सेक्टर की कुल आय में लगभग 12 प्रतिशत की बढ़त हो सकती है, लेकिन शुद्ध मुनाफा करीब 5 प्रतिशत घटने का अनुमान है। ऐ बि टिडा लगभग स्थिर रहने की संभावना है। लागत बढ़ने के कारण ऑपरिंग मार्जिन घटकर लगभग 10 प्रतिशत रह सकता है। केबल और वायर सेगमेंट में जनवरी और फरवरी में इंडेक्स्ट्रकर, रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल सेक्टर से मजबूत मांग देखने को मिली। लेकिन मार्च में वेस्ट एशिया संकट से सप्लाई में बाधा आई और मिडिल ईस्ट के लिए एक्सपोर्ट प्रभावित हुए। साथ ही कॉपर और एल्यूमिनियम जैसी कच्ची वस्तुओं की कीमतें बढ़ी, जिससे लागत और मार्जिन पर दबाव पड़ा। एयर कंडीशनर की मांग उतर और मध्य भारत में गर्मी के शुरुआती दिनों में बढ़ी, लेकिन मार्च के अंत में बेमौसमी बारिश से मांग अचानक कमजोर हो गई। दक्षिण और पूर्व भारत में गर्मी देर से आई, जबकि पश्चिम भारत में स्थिति सामान्य रही। वॉशिंग मशीन की मांग सामान्य रही, जबकि टीवी और फ्रिज की मांग आईपीएल सीजन और बढ़ते तापमान के कारण धीरे-धीरे सुधार दिखाने लगी। एफएमईजी सेगमेंट में जैसे फैन, लाइट और स्विच, कमजोर उपभोक्ता भावना के कारण मांग कमजोर रही। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने इस सेगमेंट के मार्जिन पर भी दबाव डाला।

अमेरिकी अदालत में गौतम-सागर अदाणी की एसईसी याचिका पर सुनवाई तय

अदाणी पक्ष अब 30 अप्रैल तक फाइलन मोशन दाखिल कर मामले को खारिज कराने की दलीलें पेश करेगा

न्यूयॉर्क ।

अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनियमन आयोग (एसईसी) द्वारा दायर धोखाधड़ी मामले में उद्योगपति गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर अदाणी ने अमेरिकी अदालत से याचिका खारिज करने की अनुमति मांगी। न्यूयॉर्क की पूर्वी जिला अदालत ने प्रतिवादिनों की प्री-मोशन कॉन्फ्रेंस याचिका को मंजूरी देते हुए दोनों पक्षों को बातचीत का समय तय करने का निर्देश दिया। मुकदमा

नवंबर 2024 में शुरू हुआ था। एसईसी का आरोप है कि अदाणी समूह ने भारत में सौर ऊर्जा टैके प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को कथित रूप से 25 करोड़ डॉलर से अधिक की रिश्वत देने का प्रयास किया और अमेरिकी निवेशकों तथा बैंकों को योजना की जानकारी नहीं दी। अदाणी समूह ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिकी विदेशी भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कोई उल्लंघन नहीं हुआ। अदाणी के वकीलों ने कहा कि मामला पूरी तरह भारत में



बातचीत का समय तय करने का निर्देश दिया। अदाणी पक्ष अब 30 अप्रैल तक फाइलन मोशन दाखिल कर मामले को पूरी तरह खारिज कराने की दलीलें पेश करेगा।

युद्धविराम से कच्चा तेल छह प्रतिशत टूटकर निचले सर्किट में पहुंचा

कच्चे तेल के अनुबंध का वायदा भाव 640 रुपये टूटकर 10,029 रुपये प्रति बैरल

नई दिल्ली ।

अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा के बाद वैश्विक बाजारों में कमजोरी के बीच बुधवार को कच्चे तेल के वायदा भाव में तेज गिरावट आई और यह छह प्रतिशत लुढ़ककर निचले सर्किट स्तर पर आ गया। मटटी कर्मोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर अप्रैल में आपूर्ति वाले कच्चे तेल के अनुबंध का वायदा भाव 640 रुपये या छह प्रतिशत टूटकर 10,029 रुपये प्रति बैरल पर आ गया जो इसका निचला सर्किट स्तर है। इसी तरह मई में आपूर्ति वाला अनुबंध भी 565 रुपये फिसलकर 8,860 रुपये प्रति बैरल के निचले सर्किट स्तर पर



पहुंच गया। तनाव कम होने से आपूर्ति बाधित होने की आशंकाएं घटने के बीच बाजार में तेज बिकवाली देखी गई। वैश्विक बाजारों में भी अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम की घोषणा के बाद तेल कीमतों में गिरावट आई। इससे होमूज जलडमरूमध्य से आपूर्ति सामान्य होने की उम्मीद बढ़ी है। यह मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के करीब पांचवें हिस्से के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मई में आपूर्ति वाला वेस्ट टेक्ससास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) कच्चा तेल 17.11 डॉलर या 15.15 प्रतिशत फिसलकर 95.84 डॉलर प्रति बैरल रह गया। वहीं जून में आपूर्ति वाले ब्रेंट क्रूड के अनुबंध का भाव 14.52



आरबीआई का 2026-27 में भारत की आर्थिक वृद्धि 6.9 फीसदी रहने का अनुमान

मुंबई ।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। यह वित्त वर्ष 2025-26 के अनुमानित 7.6 प्रतिशत से कम है। आरबीआई ने इसे पश्चिम एशिया संकट, जिस की ऊंची कीमतों और आपूर्ति श्रृंखला में

व्यवधान जैसी वैश्विक चुनौतियों से जोड़कर बताया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि प्रमुख समुद्री मार्गों में व्यवधान और बढ़ी हुई दुलाई एवं बीमा लागत से माल निर्यात पर दबाव पड़ सकता है। ऊर्जा और अन्य जिस की ऊंची कीमतें, साथ ही होमूज जलडमरूमध्य में व्यवधान, घरेलू उत्पादन की गति को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा वैश्विक

वित्तीय बाजारों में बढ़ती अस्थिरता भी वृद्धि संभावनाओं पर दबाव डाल रही है। मल्होत्रा ने बताया कि घरेलू मांग को कई कारक समर्थन देंगे- * सेवा क्षेत्र की मजबूती * माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों का युक्तिकरण * विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग में वृद्धि * वित्तीय संस्थानों और

कॉरपोरेट के मजबूत बही-खाते इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2026-27 में रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयास दीर्घकालिक वृद्धि के लिए सकारात्मक हैं। तिमाही आधार पर वृद्धि का अनुमान- आरबीआई के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में तिमाही आधार पर वृद्धि दर का अनुमान इस प्रकार है-



* पहली तिमाही- 6.8 फीसदी * दूसरी तिमाही 6.7 फीसदी * तीसरी तिमाही- 7.0 फीसदी * चौथी तिमाही 7.2 फीसदी

आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया बदलाव, 5.25 फीसदी पर बरकरार

ईएमआई में राहत, मिडिल ईस्ट तनाव और महंगाई के जोखिम के बीच आरबीआई ने अपनाया सतर्क रुख

नई दिल्ली ।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली द्विमासिक बैठक में प्रमुख नीतिगत दर रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर यथावत रखने का फैसला किया है। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और भू-राजनीतिक तनावों के मद्देनजर नियंत्रण लिया गया है। भारतीय

रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 6 से 8 अप्रैल तक चली बैठक के बाद यह स्पष्ट किया कि फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। समिति ने रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा है, जबकि स्टैंडिंग डिफॉजिट फेसिलिटी (एसडीएफ) दर 5 प्रतिशत और मार्जिनल स्टैंडिंग फेसिलिटी तथा बैंक दर 5.5 प्रतिशत पर स्थिर रखी गई है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा

ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है। हालांकि, अर्थव्यवस्था की हलचल को और जटिल बना रही हैं। वहीं वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव जारी है और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई को लेकर चिंता कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे माहौल में, मजबूत घरेलू बुनियादी के बावजूद भारत को वैश्विक चुनौतियों के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होगा।

इससे कीमतों में अनिश्चितता बनी हुई है। इसके साथ ही वैश्विक सप्लाई चेन में आ रही दिक्कतें हलचल को और जटिल बना रही हैं। वहीं वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव जारी है और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई को लेकर चिंता कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे माहौल में, मजबूत घरेलू बुनियादी के बावजूद भारत को वैश्विक चुनौतियों के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होगा।

एमपीसी बैठक का नतीजा बिजनेस स्टैंडर्ड्स के सर्वे के मुताबिक रहा। सर्वे 10 अर्थशास्त्रियों के बीच किया गया था। इसमें सभी प्रतिभागियों ने कहा था कि मौद्रिक नीति समिति निरंतर रेपो दर को 5.25 फीसदी पर अपरिवर्तित रख सकती है क्योंकि वह युद्ध के वृद्धि और मुद्रास्फीति पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर रही है।

आरबीएल बैंक को छोड़कर सर्वेक्षण में शामिल सभी प्रतिभागियों का कहना था कि मौद्रिक नीति पर तटस्थ रुख में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि न्यूट्रल रुख केंद्रीय बैंक को जरूरत के हिसाब से किसी भी दिशा में कदम उठाने की सहूलियत देता है। रेपो रेट वह दर है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को कर्ज देता है। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब

पर पड़ता है। जब रेपो रेट बढ़ती है, तो बैंक भी लोन महंगे कर देते हैं, जिससे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई बढ़ जाती है। इसके उलट, जब रेपो रेट घटती है तो लोन सस्ते हो जाते हैं और ईएमआई का बोझ कम हो सकता है। हालांकि, इस स्थिति में सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) पर मिलने वाला ब्याज भी कम हो सकता है।



संक्षिप्त समाचार

नाइजीरिया : पुलिस-नागरिकों पर हमले, 26 मारे

अबुजा, एजेंसी। उत्तरी नाइजीरिया में तीन अलग-अलग हमलों में 26 की मौत हो गई। नाइजीरियाई सेना ने कहा, शनिवार को उत्तर-मध्य बेनु प्रान्त के ग्वेर वेस्ट क्षेत्र में म्बालोम समुदाय 17 लोग मारे गए। उत्तर-पूर्व स्थित बोनी प्रान्त में इसी दिन पुलिस और आर्डीएस से जुड़े समूह में लंबी मुठभेड़ में 4 पुलिस अफसर मारे गए। रविवार को अरिको गांव में ईस्टर के मौके पर एक प्रार्थना सभा में पांच लोगों की हत्या कर दी गई।

पाकिस्तान : दियामेर बांध पर अशांति बढ़ी प्रदर्शनकारियों ने रोका काराकोरम मार्ग

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में दियामेर बांध से प्रभावित समुदायों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने दियामेर जिले में काराकोरम राजमार्ग (केकेएच) के कई हिस्सों को अवरुद्ध कर दिया और मार्गें पूरी नहीं होने पर उन्होंने बांध निर्माण स्थल की ओर मार्च किया। इस दौरान बांध प्रभावित समिति ने 'हुकूक दो, बांध बनाओ' जैसे नारे भी लगाए। दियामेर-भाशा बांध प्रभावित समिति विलास और थोरे में लगातार पांच दिनों से धरना दे रही है। यह आंदोलन पिछले साल संघीय सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए समझौते के लागू न होने के विरोध में शुरू हुआ था। आयोजकों ने कहा-विलास, गोराम फार्म, गहरीबद और आसपास के इलाकों के निवासी धरने में शामिल होने थोरे घाटी पहुंचे।

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से कहा टीटीपी को आतंकी गुट घोषित करें

लाहौर, एजेंसी। पाकिस्तान ने मांग की है कि अफगानिस्तान, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को औपचारिक रूप से आतंकी संगठन घोषित करे और दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने की शर्त के तौर पर उसके बुनियादी ढांचे को खत्म करे। ये बातचीत चीन में हुई थी।

चीन में नया ट्रेंड, प्रियजनों की अस्थियों को खाली पलैट में रखने लगे हैं लोग

बीजिंग, एजेंसी। चीन में बदलते हालात के बीच एक चौकाने वाला नया ट्रेंड सामने आया है। अंतिम संस्कार की बढ़ती लागत और कब्रिस्तान में जगह की कमी के चलते कई परिवार अपने प्रियजनों की अस्थियों को खाली पलैट में रखने लगे हैं। अब सरकार ने इस पर नया कानून बनाकर प्रथा पर लगातार कसने की तैयारी की है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, बीन एश अपार्टमेंट्स के नाम से पहचाने जाने वाले इन पलैट्स में रिश्तेदारों की अस्थियों के कलश रखकर धार्मिक रस्में निभाई जाने लगी हैं। इस ट्रेंड का कारण आर्थिक दबाव है क्योंकि संपत्ति के दाम 40 फीसदी तक गिरे हैं। सरकार यहां भी धार्मिक गतिविधियों को अंजाम देने से रोकने जा रही है।

पाकिस्तान में ऊर्जा बचाने के लिए मार्केट और मॉल जल्दी बंद होंगे

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान सरकार ने ईंधन संकट के चलते बाजार और शॉपिंग मॉल जल्दी बंद करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री शेहबाज शरीफ की अध्यक्षता में इस पर बैठक हुई। पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद और पाकिस्तान-नियंत्रित कश्मीर में मार्केट और मॉल मंगलवार से रात 8 बजे बंद होंगे। खैबर-पख्तूनख्वा में मुख्य शहरों में 9 बजे तक खुलने की छूट रहेगी। सिंध में समय तय करने के लिए मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने व्यवसाय प्रतिनिधियों से परामर्श लेने की बात कही। बेकरी, रेस्टोरेंट और खाने-पीने की दुकानों को रात 10 बजे बंद करने का निर्णय लिया गया। शादी हॉल भी रात 10 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर और फार्मसियों पर समय का प्रतिबंध नहीं होगा। सरकार का उद्देश्य ईंधन की खपत कम करना और विदेशी मुद्रा बचाना है।

वेनेजुएला की डेलसी रोड्रिगज अभी भी कार्यवाहक राष्ट्रपति

काराकास, एजेंसी। वेनेजुएला में डेलसी रोड्रिगज 90 दिनों की अंतरिम अवधि पूरी होने के बाद भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निकोलस माद्रुरो अभी भी राष्ट्रपति हैं, लेकिन उनकी जबरन अनुपस्थिति के कारण उप-राष्ट्रपति की भूमिका रोड्रिगज ने संभाली। अंतरिम नियुक्ति 90 दिनों तक होती है, और राष्ट्रीय सभा इसे 90 दिन और बढ़ा सकती है। राष्ट्रपति माद्रुरो और उनकी पत्नी को जनवरी में न्यूयॉर्क में दूग से जुड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए ले जाया गया। दोनों निर्दोष होने का दावा कर चुके हैं।

ट्रंप के हमलों से निपटने के लिए ईरान में बनेगी मानव श्रृंखला, ढाल का करेंगे काम

तेहरान, एजेंसी। पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। अमेरिका और इराक के हमले तीव्र हो गए हैं, मिसाइलें आसमान में झूल रही हैं और धमाके शहरों में भय और तबाही फैला रहे हैं। तेल और गैस की आपूर्ति खतरे में है, वैश्विक बाजार अस्थिर हैं। होमुज जलसंधि की ब्लॉकिंग से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव बढ़ रहा है। हर पल संघर्ष और विकराल होता जा रहा है और शांति के संकेत कहीं नजर नहीं आते। ट्रंप की डेडलाइन से पहले ईरान ने अपनाई मानव श्रृंखला बनाने की योजना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा होमुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की समयसीमा नजदीक आने से पहले ईरान ने बड़ी योजना बनाई है। तेहरान ने कथित तौर पर युवा इरानियों से ईरान के प्रमुख बिजली संयंत्रों के चारों ओर प्रतीकात्मक मानव श्रृंखला बनाने का आह्वान किया है। ईरान के खेल और युवा मंत्रालय ने एथलीटों, कलाकारों और छात्रों सहित देश के युवाओं से मंगलवार को दोपहर दो बजे (स्थानीय समय) से इन स्थलों के आसपास इकट्ठा होने का आह्वान किया है। ईरान के युवा मामलों के उप मंत्री अलीरजा रहमी ने एक वीडियो संदेश में कहा, 'कई विश्वविद्यालय के युवाओं, युवा कलाकारों और युवा संगठनों ने प्रस्ताव दिया कि हम देश के बिजली संयंत्रों के चारों ओर एक मानव घेरा या मानव श्रृंखला बनाएं। न्यूजीलैंड बोला-ईरानी बुनियादी ढांचे के खिलाफ अमेरिकी

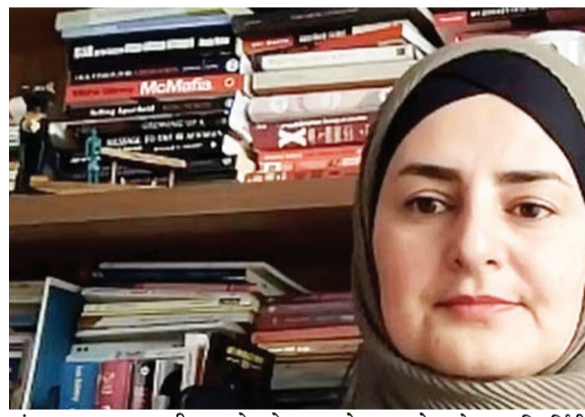


धमकियां 'निरर्थक' न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने ईरानी नागरिक अवसरंचना के खिलाफ ट्रंप की हालिया धमकियों को निरर्थक बताया है। उन्होंने कहा कि यह मददगार नहीं है, क्योंकि और अधिक सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि मूल बात यह है कि इस संघर्ष को और अधिक फैलने से रोकने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।' उन्होंने कहा कि इस सप्ताह वाशिंगटन में होने वाली बैठक न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री बिंस्टन पीटर्स का अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को संदेश होगा कि संघर्ष को कम किया जाए। ईरान ने जनवरी से हिरासत में

लक्ष्यों पर हमले किए हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए जिम्मेदार और ईरान पर हमलों का नेतृत्व कर रही अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसकी सेनाओं ने 13,000 से अधिक ईरानी ठिकानों पर हमला किया है। सेंट्रल कमांड ने यह भी कहा कि 155 से अधिक ईरानी जहाजों को नुकसान पहुंचाया गया है या नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिकी परमाणु-संचालित विमानवाहक पोत और पनडुब्बियां ऑपरेशन एफिक पयूरी में भाग ले रही हैं। इसके साथ ही एफ-35 स्टील्थ फाइटर जेट से लेकर बी-52 बमबर्षक विमानों तक का एक बेड़ा भी इसमें शामिल है। इराक में ड्रोन हमले में पति-पत्नी की मौत, ईरान पर आरोप इराक के उत्तरी हिस्से में एक बड़ा हमला सामने आया है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, एरबिल प्रांत में ईरान की ओर से आए ड्रोन हमले में दो नागरिकों की मौत हो गई। बताया गया कि यह हमला दार रात हुआ, जब एक विस्फोटक से भरा ड्रोन एरबिल के दरशाकरान इलाके के जराका जोंग गांव में एक घर पर गिरा। इस हमले में एक शादीशुदा जोड़े की जान चली गई। एरबिल के गवर्नर और पूर्व खोशनांव ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और युद्ध अपराध बताया है। स्थानीय सुरक्षा एजेंसियां इस हमले की जांच कर रही हैं और मामले को गंभीर मान रही हैं।

सिर पर बंदूक रखकर बातचीत नहीं: सेतारेह सादेकी ट्रंप की धमकियों पर फिर भड़का ईरान, तेहरान की महिला प्रोफेसर का कड़ा जवाब

तेहरान, एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी चेतावनियों पर ईरान से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। तेहरान विश्वविद्यालय की महिला सहायक प्रोफेसर सेतारेह सादेकी ने साफ कहा कि हमारे सिर पर बंदूक रखकर बातचीत की बात करना ईरान के लिए कभी स्वीकार्य नहीं होगा।



दरअसल, ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि यदि मंगलवार रात तक कोई समझौता नहीं हुआ तो ईरान के बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान डालना पड़ेगा। उन्होंने यहां तक कहा कि एक रात में ईरान को खत्म कर सकते हैं।

धमकियों के बीच बातचीत नहीं: सादेकी ने कहा कि अमेरिका की ये धमकियां कोई नई बात नहीं हैं, बल्कि पहले दिए गए डेडलाइन का विस्तार हैं। उनके मुताबिक ईरान इसे ऐसे देखा है जैसे हमारे सिर पर

ईरान देगा जवाब : उन्होंने यह भी कहा कि ईरान ने पहले भी अमेरिकी हमलों का जवाब प्रभावी तरीके से दिया है। ईरान ने क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और इस्राइली इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर अपनी क्षमता दिखाई है। सादेकी ने चेतावनी दी कि ईरान भविष्य में भी ऐसे ही जवाब देगा जिससे अमेरिका की हमले करने की क्षमता कमजोर हो सके।

ट्रंप का अल्टीमेटम और 'क्रिटिकल पीरियड': व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह क्रिटिकल पीरियड है और ईरान को समझौते के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। उन्होंने कहा हमने उन्हें 10 दिन दिए हैं। अब उनके पास मंगलवार रात 8 बजे (ईस्टर्न टाइम) तक का समय है। इसके बाद उनके पास न पुल होंगे, न पावर प्लांट।

ईरानी बुनियादी ढांचों पर हमले की अमेरिकी धमकी से संयुक्त राष्ट्र चिंतित, प्रवक्ता ने जताई आपत्ति

जिनेवा, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका के उस बयान पर चिंता जताई है, जिसमें ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों पर हमले की धमकी दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह की भाषा को तय करना कि यह अपराध है या नहीं, अदालत का काम है। उन्होंने साफ कहा, 'किसी भी नागरिक ढांचे पर हमला करना अंतरराष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। इस बीच, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरगची ने तेहरान स्थित शरिफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर अमेरिका और इजरायल के हमले की कड़ी निंदा की। इस वार्ता में कहा, 'सोशल मीडिया पर किए गए इस पोस्ट में अमेरिका द्वारा बिजली संयंत्रों, पुलों और अन्य ढांचों पर हमले की बात कही गई थी, जिसे लेकर हम चिंतित हैं, खासकर अगर ईरान किसी समझौते के लिए तैयार नहीं होता।' उन्होंने कहा कि महासचिव पहले भी साफ कर चुके हैं कि अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन जरूरी है और सभी पक्षों को संघर्ष के दौरान अपने दायित्वों का सम्मान करना चाहिए। प्रवक्ता के मुताबिक, गुटरेस ने दोहराया कि आम लोगों से जुड़ी सुविधाओं, जैसे बिजली और ऊर्जा से जुड़े ढांचे, पर हमला नहीं किया जाना चाहिए, भले ही कुछ मामलों में उन्हें सैन्य लक्ष्य माना जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि सभी पक्ष इस संघर्ष को खत्म करें,

क्योंकि अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान ही सबसे सही रास्ता है। जब यह पूछा गया कि क्या ऐसे हमले युद्ध अपराध माने जाएंगे, तो दुर्जाकिर ने कहा कि ये अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होंगे। यह तय करना कि यह अपराध है या नहीं, अदालत का काम है। उन्होंने साफ कहा, 'किसी भी नागरिक ढांचे पर हमला करना अंतरराष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। इस बीच, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरगची ने तेहरान स्थित शरिफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर अमेरिका और इजरायल के हमले की कड़ी निंदा की। इस वार्ता में कहा, 'सोशल मीडिया पर किए गए इस पोस्ट में अमेरिका द्वारा बिजली संयंत्रों, पुलों और अन्य ढांचों पर हमले की बात कही गई थी, जिसे लेकर हम चिंतित हैं, खासकर अगर ईरान किसी समझौते के लिए तैयार नहीं होता।' उन्होंने कहा कि महासचिव पहले भी साफ कर चुके हैं कि अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन जरूरी है और सभी पक्षों को संघर्ष के दौरान अपने दायित्वों का सम्मान करना चाहिए। प्रवक्ता के मुताबिक, गुटरेस ने दोहराया कि आम लोगों से जुड़ी सुविधाओं, जैसे बिजली और ऊर्जा से जुड़े ढांचे, पर हमला नहीं किया जाना चाहिए, भले ही कुछ मामलों में उन्हें सैन्य लक्ष्य माना जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि सभी पक्ष इस संघर्ष को खत्म करें,

यहां एक बड़ी कब्रगाह बनाई जाएगी। इसमें यह भी कहा गया है कि खमेनेई परिवार के अन्य लोग और मौत के बाद मोजतबा को भी यहीं दफनाना जाएगा। ईरान ने पहले ही यह कन्फर्म कर दिया था कि जिस एयरस्ट्राइक में मोजतबा के पिता अली खामेनेई, मां और पत्नी जहाद हद्दा आदेल मारी गई थीं। उसमें मोजतबा भी घायल हुए थे। जब से मोजतबा का नाम सुप्रीम लीडर के तौर पर आगे किया गया है तब से ही वह सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। अब इसको लेकर कई तरह के चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

एक दिन पहले जारी किया गया था मोजतबा का बयान : एक दिन पहले ही ईरान के अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने सार्वजनिक बयान जारी कर रिवोल्यूशनरी गार्ड से खुफिया प्रमुख के मारे जाने पर शोक व्यक्त किया। खामेनेई ने सोशल मीडिया मंच पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि मेजर जनरल मजीद खामदी अपने प्राण न्योछावर करने वाले 'योद्धाओं और लड़ाकों की पवित्र' में शामिल हो गए हैं। बता दें कि अमेरिका ने ईरान को मंगलवार रात 8 बजे तक का समय दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर इस समय के भीतर ही होमुज को खोलने का समझौता नहीं होता है तो ईरान के सारे पुल और पावर प्लांट ध्वस्त कर दिए जाएंगे।

ईरान के सुप्रीम लीडर को मार गया लकवा, बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती: रिपोर्ट

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध के बीच ईरान में सुप्रीम लीडर को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को यह जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उनकी हालत ठीक नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक वह बेहोश हैं और कोम शहर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूएसएस और इजरायली इंटीलिजेंस ने अपने सहयोगी खाड़ी देशों को बताया है कि मोजतबा खामेनेई की हालत बेहद खराब है और इस स्थिति में वह कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं। हालांकि ईरान की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की

गई है। युद्ध के समय कई बार ऐसी खबरें मनोवैज्ञानिक हमला करने के लिए भी फैलाई जाती हैं।

पहली बार लोकेशन की जानकारी : रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया एजेंसियों की तरफ से दिए गए मेमो में कहा गया है कि उनकी हालत लकवा मारने जैसी है और वह कुछ भी सोचने-समझने के लायक नहीं बचे हैं। पहली बार है जब सुप्रीम लीडर की लोकेशन के बारे में भी जानकारी दी गई है।

बनाई जा रही कब्रगाह : बता दें कि कोम ईरान का पवित्र शहर है। इंटीलिजेंस मेमो में कहा गया है कि अली खामेनेई को भी कोम में दफनाने की तैयारी चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक

यहां एक बड़ी कब्रगाह बनाई जाएगी। इसमें यह भी कहा गया है कि खमेनेई परिवार के अन्य लोग और मौत के बाद मोजतबा को भी यहीं दफनाना जाएगा। ईरान ने पहले ही यह कन्फर्म कर दिया था कि जिस एयरस्ट्राइक में मोजतबा के पिता अली खामेनेई, मां और पत्नी जहाद हद्दा आदेल मारी गई थीं। उसमें मोजतबा भी घायल हुए थे। जब से मोजतबा का नाम सुप्रीम लीडर के तौर पर आगे किया गया है तब से ही वह सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। अब इसको लेकर कई तरह के चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

एक दिन पहले जारी किया गया था मोजतबा का बयान : एक दिन पहले ही ईरान के अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने सार्वजनिक बयान जारी कर रिवोल्यूशनरी गार्ड से खुफिया प्रमुख के मारे जाने पर शोक व्यक्त किया। खामेनेई ने सोशल मीडिया मंच पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि मेजर जनरल मजीद खामदी अपने प्राण न्योछावर करने वाले 'योद्धाओं और लड़ाकों की पवित्र' में शामिल हो गए हैं। बता दें कि अमेरिका ने ईरान को मंगलवार रात 8 बजे तक का समय दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर इस समय के भीतर ही होमुज को खोलने का समझौता नहीं होता है तो ईरान के सारे पुल और पावर प्लांट ध्वस्त कर दिए जाएंगे।

अमेरिका-भारत संबंधों में तेजी आने के साथ ही प्राथमिकताओं के तालमेल पर जोर

वाशिंगटन, एजेंसी। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने अपनी रणनीतिक साझेदारी में नई गति का संकेत दिया है। यह संकेत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के लिए आयोजित व्हाइट हाउस रात्रिभोज से पहले मिला। वहीं वाशिंगटन में हुई उच्चस्तरीय बैठकों की श्रृंखला ने सुरक्षा और राजनीतिक प्राथमिकताओं पर बढ़ती समानता को भी रेखांकित किया। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति भारत में अमेरिकी राजदूत के साथ एक रात्रिभोज में भाग लेने वाले हैं। गोर इस समय अमेरिकी राजधानी में हैं और कई बैठकों में शामिल हो रहे हैं। गोर ने वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों, जिनमें एफबीआई निदेशक काश पटेल भी शामिल हैं, के साथ बैठकों के बाद सहयोग के विस्तार पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उन्होंने 'रचनात्मक चर्चा' की, जिसमें 'सीमा पार खतरों, साइबर अपराध, मादक पदार्थों और अवैध

नेटवर्क' से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने कहा, 'सुरक्षा प्राथमिकताओं पर मजबूत तालमेल है,' और जोड़ कि पटेल 'एफबीआई में शानदार काम कर रहे हैं।' उन्होंने हालिया कानून-प्रवर्तन उपलब्धियों का भी उल्लेख किया और कहा: '2025 में: हिंसक अपराधों में गिरफ्तारियों में साल-दर-साल 112% की वृद्धि। हत्याओं में 20 प्रतिशत की कमी। डकैती में 20 प्रतिशत की कमी।' ये संकेत वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच साझा सुरक्षा चुनौतियों, विशेष रूप से साइबर खतरों और संगठित अपराधिक नेटवर्क के खिलाफ परिचालन सहयोग को गहरा करने के व्यापक प्रयासों के बीच हो रहे हैं। गोर ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ अपनी बैठक के बाद संबंधों के राजनीतिक पहलू पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, 'अभी-अभी उपराष्ट्रपति के साथ शानदार बैठक समाप्त हुई। अमेरिका-भारत संबंधों



पर उपराष्ट्रपति के निरंतर नेतृत्व और ध्यान के लिए धन्यवाद।' उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में व्हाइट हाउस इस क्षेत्र में पूरी तरह सक्रिय है,' और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र तथा उसमें भारत की भूमिका पर अमेरिका के निरंतर ध्यान की ओर इशारा किया।

कूटनीतिक प्रयासों में गोर और अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वारा के बीच बैठक भी शामिल रही, जो दोनों पक्षों के बीच करीबी समन्वय को दर्शाती है। गोर ने कहा, 'मेरे मित्र क्वारा से मिलकर हमेशा खुशी होती है। वे हमारे रणनीतिक संबंधों की गहराई से परवाह करते हैं।' क्वारा ने इस बातचीत को दोनों लोकतंत्रों के बीच संबंधों को मजबूत करने के जारी प्रयासों का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा, 'वाशिंगटन डीसी की यात्रा के दौरान अपने मित्र, राजदूत सर्जियो गोर से मिलकर खुशी हुई। उनके सहयोग का सम्मान करता हूँ और हम दोनों देशों के नेताओं द्वारा तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपने मजबूत प्रयास जारी रखेंगे।' ये बातचीत सुरक्षा, कूटनीति और राजनीतिक नेतृत्व को शामिल करते हुए बहु-स्तरीय जुड़ाव को दर्शाती है, जिसमें दोनों पक्ष प्रमुख प्राथमिकताओं पर तालमेल पर जोर दे रहे हैं।

ट्रंप ने समयसीमा तय की ईरान पर हमलों की चेतावनी दी



वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को समझौता करने के लिए अंतिम समयसीमा दी है और चेतावनी दी है कि अगर बातचीत विफल होती है तो व्यापक सैन्य कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच यह कदम उठाया गया है, जिसका वैश्विक ऊर्जा और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा, 'उनके पास कल तक का समय है और जोड़ कि कूटनीतिक की गुंजाइश तेजी से खत्म हो रही है। उन्होंने बताया कि बातचीत जारी है लेकिन अनिश्चित बनी हुई है। उन्होंने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से कहा 'हमें लगता है कि वे ईमानदारी से बातचीत कर रहे हैं... हमें जल्द ही पता चल जाएगा। इसके साथ ट्रंप ने साफ किया कि सैन्य विकल्प अब भी खुले हैं। 'हम उन्हें बुरी तरह हिला सकते हैं,' उन्होंने कहा, संभावित अमेरिकी कार्रवाई के पैमाने को रेखांकित करते हुए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि संभावित लक्ष्यों के मामले में 'बहुत कम चीजें सीमा से बाहर हैं,' जिससे संकेत मिलता है कि यदि ईरान ने पालन नहीं किया तो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर भी हमला किया जा सकता है। राष्ट्रपति ने संकेत दिया कि तेल की निबंध आपूर्ति सुनिश्चित करना अमेरिका की मांगों का एक प्रमुख हिस्सा है।

'उस समझौते का एक हिस्सा यह होगा कि हम तेल और अन्य चीजों की मुक्त आवाजाही चाहते हैं।' उन्होंने कहा, 'और होमुज जलडमरूमध्य जैसे ऊर्जा मार्गों के रणनीतिक महत्व की ओर इशारा किया। ट्रंप ने हालिया अमेरिकी अभियानों के बाद ईरान को कमजोर बताया। उन्होंने कहा, 'उनके पास नौसेना नहीं है... उनके पास वायु सेना नहीं है... उनके पास वायु रक्षा प्रणाली नहीं है।' हालांकि उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अतंममित खतरे अब भी मौजूद हैं। उन्होंने संघर्ष के अगले चरण को लेकर अनिश्चितता भी स्वीकार की। ट्रंप ने कहा, 'मैं आपको नहीं बता सकता... यह इस पर निर्भर करता है कि वे क्या करते हैं।' ये टिप्पणियां दबाव और कूटनीतिक के मिश्रण को दर्शाती हैं, जहां अमेरिका रियायतें हासिल करने की कोशिश कर रहा है, साथ ही हमलों को तेज करने का विकल्प भी खुला रख रहा है। ट्रंप ने कहा कि कई देश इस संकट के समाधान के प्रयासों में लगे हुए हैं। 'इस युद्ध से बहुत से लोग प्रभावित हो रहे हैं।' यह स्थिति वैश्विक ऊर्जा बाजारों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है, खासकर यदि तनाव के कारण होमुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों में बाधा आती है, जो तेल आपूर्ति की एक प्रमुख धुरी है।

सीजफायर होते ही ईरान में भारतीय दूतावास ने जारी की चेतावनी.....जल्द से जल्द देश छोड़ दें

तेहरान ।

ईरान में सुरक्षा स्थिति को लेकर भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। सीजफायर के कुछ घंटे बाद जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि ईरान में मौजूद भारतीय जल्द से जल्द देश छोड़ दें और दूतावास द्वारा सुरक्षा गैर सुरक्षित मार्गों का पालन करें। यह सलाह 7 अप्रैल 2026 को जारी की गई पिछली एडवाइजरी को बढ़ाकर दी गई है।

ईरान में भारतीय दूतावास ने विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास जाने से पहले उनसे समन्वय करने पर जोर दिया है। इससे पहले जारी एडवाइजरी में कहा गया था कि ईरान में रहने वाले भारतीय अगले 48 घंटों तक वहीं बने रहें, बिजली और सैन्य ठिकानों से दूर रहें और बहुमंजिला इमारतों की ऊपरी मंजिलों पर न जाएं। होटलों में ठहरे लोगों को कमरे में ही रहने और दूतावास के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने की सलाह दी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरानी ठिकानों पर हमले के बाद संघर्ष शुरू हुआ। तब ईरान में लगभग 9,000 भारतीय मौजूद थे, जिसमें अधिकांश छात्र हैं। अब तक करीब 1,800 भारतीय सुरक्षित रूप से भारत लौट चुके हैं। इस स्थिति में दूतावास ने नागरिकों से आधिकारिक अपडेट पर लगातार नजर रखने और किसी भी तरह के जोखिम भरे क्षेत्र में जाने से बचने की अपील की है। सीजफायर के

बावजूद सुरक्षा की अनिश्चितता बनी हुई है, इसलिए दूतावास की सलाह का पालन करना आवश्यक है। ईरान में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित और तेजी से देश छोड़ने की सलाह दी जा रही है, सीमा पर जाने से पहले दूतावास से समन्वय आवश्यक है, और आधिकारिक निर्देशों पर लगातार ध्यान रखना अनिवार्य है। इस समय भारतीय नागरिकों के लिए प्राथमिकता उनकी सुरक्षा और सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करना है।

अजित पवार के विमान हादसे को लेकर भ्रामक वीडियो बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार मुंबई ।



कीटों का स्वर्ग' नहीं, जैविक खेती से सिविकम बना टिकाऊ कृषि का मॉडल

100 फीसद ऑर्गेनिक राज्य बनने के बाद बढ़ी जैव विविधता, किसानों की आय और इको-टूरिज्म को मिला बढ़ावा

गंगटोक ।

सिक्किम को लेकर अक्सर यह दावा किया जाता है कि जैविक खेती ने इसे कीटों का स्वर्ग बना दिया है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। वर्ष 2016 में भारत का पहला 100 फीसद प्रमाणित जैविक राज्य बनने के बाद सिक्किम ने न केवल पर्यावरण संरक्षण में मिसाल पेश की, बल्कि टिकाऊ कृषि का सफल मॉडल भी स्थापित किया। राज्य सरकार ने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग और बिजली पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। इसके स्थान पर वर्मीकम्पोस्ट, नीम-आधारित जैविक कीटनाशक और गोबर से बनी खाद को बढ़ावा दिया गया। इस बदलाव का सकारात्मक असर मिट्टी की गुणवत्ता पर पड़ा, जिससे उसकी उर्वरता में सुधार हुआ और जल स्रोतों का प्रदूषण कम हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार, जैविक खेती के कारण पराणुकों-जैसे मधुमक्खियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है। इसके साथ ही जैव विविधता में भी इजाफा हुआ है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बेहतर बना है। आर्थिक दृष्टि से भी यह परिवर्तन लाभकारी साबित हुआ है। जैविक उत्पादों को बाजार में प्रीमियम मूल्य मिलने से किसानों की आय में वृद्धि हुई है। साथ ही, राज्य में इको-टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला है, जिससे पर्यटन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वैश्विक स्तर पर मिली सराहना सिक्किम के इस प्रयास को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन (एफएओ) ने राज्य को 'प्युचर पॉलिसे गोल्ड अवार्ड' से सम्मानित किया है। इस प्रकार सिक्किम का यह अनुभव साबित करता है कि ससायन-मुक्त खेती न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी टिकाऊ विकास का मार्ग प्रस्तुत कर सकती है।



वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवाई का निधन

नोएडा ।

कांग्रेस की दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवाई का बुधवार तड़के 4 बजे नोएडा के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहीं और उनकी गिनती कांग्रेस के उन कद्दावर नेताओं में होती थी जो गांधी परिवार के बेहद भरोसेमंद माने जाते थे। उनके निधन की खबर से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, उनके पार्थिव शरीर को आज बुधवार दोपहर तीन बजे उनके नोएडा स्थित सेक्टर-40 आवास से अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जाएगा। शाम करीब 5 बजे उन्हें

दिल्ली के निजामुद्दीन कब्रिस्तान में सुपूर्द-ए-खाक किया जाएगा। किदवाई का राजनीतिक करियर बेहद शानदार रहा; उन्होंने केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दीं और हज्रत कमेटी की अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। वे कई बार सांसद चुनी गईं और कांग्रेस संगठन में महासचिव, कांग्रेस कार्य समिति तथा केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहीं। सांसद मनीष तिवारी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें एक शहीदा और समर्पित राजनेता बताया। उन्होंने कहा कि श्रीमती किदवाई के व्यक्तित्व में सरलता और विभ्रमता का अनूठा संगम था और उनके चेहरे पर हमेशा रहने वाली आत्मीय मुस्कान उनकी



पहचान थी। उनके निधन को कांग्रेस पार्टी और भारतीय राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति बताते हुए तिवारी ने कहा कि देश की सेवा में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मोहसिना किदवाई ने अपने लंबे राजनीतिक सफर में न केवल महिला सशक्तिकरण को मिसाल पेश की, बल्कि संगठन को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाई।

अजित पवार के विमान हादसे को लेकर भ्रामक वीडियो बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार

मुंबई ।

महाराष्ट्र के जालना जिले के युवक उद्भव भगवान काप्से को सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक वीडियो बनाने और वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस वीडियो में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की छवि धूमिल करने और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार से जुड़े विमान हादसे को लेकर गलत जानकारी फैलाने का आरोप है। पश्चिमी क्षेत्रीय पुलिस विभाग की साइबर सेल ने आरोपी की पहचान कर कानूनी कार्रवाई के लिए मुंबई लाया गया। बांद्रा की अदालत ने काप्से को 10 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। 'बुई' साइबर पुलिस के अनुसार, काप्से द्वारा अपलोड किए गए वीडियो को हटाने से पहले



करीब 1.5 लाख बार देखा जा चुका था। जांच में सामने आया कि वीडियो में मुख्यमंत्री फडणवीस को निशाना बनाकर भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री थी और विमान हादसे से संबंधित तथ्य भी गलत तरीके से प्रस्तुत किए गए थे। वरिष्ठ अधिकारियों ने वायरल वीडियो का गंभीर संज्ञान लेकर साइबर सेल को केस दर्ज करने का निर्देश दिया। सोशल मीडिया से वीडियो हटवाकर एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ फर्जी

वीडियो वायरल करने और सार्वजनिक हस्तियों को बदनाम करने की एफआईआर दर्ज की गई थी। तर्कनीकी विश्लेषण से वीडियो का स्रोत जालना जिले के बुढ़गांव गांव से पाया गया। पुलिस की टीम ने काप्से को हिरासत में लिया। पूछताछ में काप्से ने स्वीकार किया कि उसने उपलब्ध फुटेज को संकलित कर एआई टूल्स की मदद से वीडियो बनाकर साझा किया।

पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में सलमान खान को राहत

जयपुर ।

पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत मिली है। यह मामला राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) में चल रहा था, जहां उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट पर फिलहाल रोक लगी है। आयोग के इस फैसले के बाद सलमान को तुरंत किसी कानूनी कार्रवाई या जेल जाने का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह पूरा विवाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 72 के तहत दर्ज हुआ था, जिसमें भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सख्त प्रावधान हैं। आरोप था कि पान मसाला के विज्ञापन में उपभोक्ताओं को गुमराह किया गया। इस मामले में पहले जिला आयोग ने सख्त रुख अपनाकर वारंट जारी किया था, लेकिन अब उच्च स्तर पर हस्तक्षेप होने से स्थिति बदल गई है।



एनसीडीआरसी की दो सदस्यीय बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एपी साहि और सदस्य भारतकुमार पांडे शामिल हैं, ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी फाइल तलब की है। आयोग ने स्पष्ट किया कि जब तक सभी तथ्यों की विस्तार से जांच नहीं हो जाती, तब तक किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक रहेगी। साथ ही, शिकायतकर्ता अधिवक्ता योगेंद्र सिंह बडियाल को नोटिस जारी किया गया है। इस केस की अगली सुनवाई 15 अप्रैल 2026 को तय की गई है, जहां आगे की दिशा स्पष्ट होगी।

हॉलमार्क के नाम पर करोड़ों की ठगी...नकली मुहर से ग्राहकों को लाखों का नुकसान

एचयूआईडी की पहचान के लिए बीआईएसएफ का करे उपयोग...असली हॉलमार्क में यूनिट आईडी

नई दिल्ली ।

सोने के गहनों पर भरोसे की सबसे बड़ी पहचान हॉलमार्क मानी जाती है, लेकिन अब यही भरोसा ठगी का जरिया बनता जा रहा है। बाजार में नकली हॉलमार्क लगाकर ज्वेलर्स ग्राहकों को चूना लगा रहे हैं। रोजाना करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी सामने आ रही है और खरीददारों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआईएस) ने 2 ग्राम से अधिक वजन के सोने के आभूषणों पर हॉलमार्क यूनिट आईडी (एचयूआईडी) अनिवार्य कर रखी है। इसके बावजूद कई दुकानों पर फर्जी हॉलमार्क के साथ 22य, 916 जैसी शुद्धता की मुहर लगाकर गहने बेचे जा रहे हैं। जांच में कई मामलों में 20-22 कैरेट बताकर बेचे गए गहने 14 या 16 कैरेट के निकले। इसका सीधा मतलब है कि 10 ग्राम सोने पर ही



ग्राहक को 30 से 50 हजार रुपये तक का नुकसान हो सकता है। फर्जी हॉलमार्क की पहचान करना आसान नहीं है। असली हॉलमार्क में बीआईएस का त्रिकोण चिन्ह, शुद्धता (जैसे 22य916), छह अंकों की यूनिट एचयूआईडी और ज्वेलर की पहचान अंकित होती है। जबकि नकली हॉलमार्क में अक्सर यूनिट आईडी नहीं होती या गलत ढंग से उकेरी जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्राहक गहना खरीदते समय पक्का बिल

सूरत में वैष्णव समाज का भव्य आयोजन, आनंद वैष्णव बने राष्ट्रीय अध्यक्ष

क्रांति समय

सूरत: शहर के सारोली स्थित लेउवा पाटीदार सांस्कृतिक भवन में रविवार को राजस्थान श्री वैष्णव चार सम्प्रदाय समाज ट्रस्ट (दक्षिण गुजरात) द्वारा हनुमान जन्मोत्सव एवं परिचय सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम को शुभआत सुबह गणेश वंदना से हुई और पूरे दिन धार्मिक व सांस्कृतिक गतिविधियों का दौर चलता रहा। कार्यक्रम में भव्य दरबार, अखंड ज्योत, छयनभोग और महाप्रसाद का आयोजन किया गया। समाज के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी

गई, वहीं राजस्थान से आए भजन गायकों ने भजनों की मधुर प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। स्थानीय कलाकारों ने भी भक्ति गीत प्रस्तुत किए। इस अवसर पर समाज के युवक-युवतियों का परिचय सम्मेलन भी आयोजित किया गया, ताकि उन्हें योग्य जीवनसाथी मिल सके। कार्यक्रम में गुजरात सहित देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में समाज बंधु शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर सर्वसम्मति से ट्रस्ट को अखिल भारतीय स्तर का दर्जा दिया गया। इस दौरान बाबरा (ब्यावर)

निवासी आनंद वैष्णव को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया, वहीं दीपक माण्डा को गुजरात प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस घोषणा पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। वक्ताओं ने समाज में एकता बनाए रखने और सामाजिक कुरीतियों से बचने का संदेश दिया। अंत में ट्रस्ट द्वारा वार्षिक लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया तथा सभी अतिथियों, समाज बंधुओं और सहयोगियों का सम्मान का सम्मान व्यक्त किया गया।



किसानों और लोगों के लिए चिंता की बात.....इस साल मानसून की बारिश सामान्य से कम रहेगी



नई दिल्ली ।

इस साल मानसून की बारिश सामान्य से कम रह सकती है। निजी मौसम एजेंसी ने इस साल के मानसून का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। इसके अनुसार, बारिश सामान्य से 6 प्रतिशत कम रह सकती है। जून से सितंबर तक मानसून के 4 महीनों में देश में बारिश का सामान्य औसत 868.6 मिलीमीटर है। सामान्य से कम मानसून का मतलब है कि बारिश 90 प्रतिशत से 95 प्रतिशत के बीच रहेगी। मौसम एजेंसी ने 94 प्रतिशत बारिश का अनुमान दिया है। मौसम एजेंसी के मुताबिक, जून में सामान्य बारिश होगी, लेकिन जुलाई से गिरावट शुरू होकर अगस्त और सितंबर में मानसून कमजोर पड़ेगा। खासकर अगस्त-सितंबर में बारिश की कमी ज्यादा रहने के संकेत हैं। मध्य और पश्चिम भारत के मुख्य क्षेत्रों में बारिश कम रहने के आसार हैं। अगस्त-सितंबर में मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सामान्य से कम बारिश की आशंका है। क्या होता है लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी एलपीए इसका मतलब है कि मौसम विभाग ने 1971-2020 की अवधि के आधार पर दक्षिण-पश्चिम मानसून के लिए लॉन्ग पीरियड एवरेज (एलपीए) को 87 सेमी (870 मिमी) निर्धारित किया है। अगर किसी साल की बारिश 87 सेमी से ज्यादा होती है, तो उसे सामान्य से अधिक माना जाता है। अगर कम होता कमजोर मानसून माना जाता है। जानकार ने कहा कि मानसून की शुरुआत के समय अल-नीनो बनने की संभावना है। इससे मानसून कमजोर पड़ सकता है। हिंद महासागर द्विध्रुव (आईओडी) मजबूत हो, तब अल-नीनो का असर कुछ कम होता है। अभी आईओडी सामान्य या थोड़ा अधिक रहने की उम्मीद है। इससे मानसून की शुरुआत ठीक होगी, लेकिन सीजन के दूसरे हिस्से में बारिश कमजोर पड़ने का खतरा रहेगा।